



Lakshya IAS

academy

08

Sep 2026

DAILY CURRENT AFFAIRS



Mr. R.P. Singh Sir
(MD)



1. उपराष्ट्रपति सी. पी. राधाकृष्णन ने असम में विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह की अध्यक्षता की

उपराष्ट्रपति सी. पी. राधाकृष्णन ने गुवाहाटी की अपनी यात्रा के दौरान असम में एक विश्वविद्यालय के दीक्षांत



समारोह की अध्यक्षता की। गुवाहाटी पहुंचने पर असम के राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य ने उनका स्वागत किया, जो सितंबर 2026 तक असम के राज्यपाल के रूप में कार्यरत हैं। यात्रा के दौरान उपराष्ट्रपति ने दीक्षांत समारोह को संबोधित किया और राष्ट्र के भविष्य को आकार देने में शिक्षा, ज्ञान, नवाचार और चरित्र निर्माण के महत्व पर प्रकाश डाला। उन्होंने विद्यार्थियों को समाज में सार्थक योगदान देने तथा लोकतांत्रिक और संवैधानिक मूल्यों को बनाए रखने के लिए प्रोत्साहित किया। इस यात्रा ने युवाओं को सशक्त बनाने और सीखने, कौशल, अनुसंधान तथा जिम्मेदार नागरिकता के माध्यम से देश के विकास को मजबूत करने में उच्च शिक्षा की भूमिका को रेखांकित किया।

मुख्य बिंदु:

- उपराष्ट्रपति की यात्रा ने प्राथमिकता सुनिश्चित की: भारत के उपराष्ट्रपति ने उच्च स्तरीय सार्वजनिक और शैक्षणिक कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए असम की दो दिवसीय आधिकारिक यात्रा शुरू की।
- शैक्षणिक दीक्षांत समारोह की अध्यक्षता: उन्होंने श्रीमंत शंकरदेव स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में भाग लिया, जिसमें स्नातक चिकित्सा विद्यार्थियों और शोधकर्ताओं को सम्मानित किया गया।

Vice President C. P. Radhakrishnan Presides Over University Convocation in Assam

Vice President C. P. Radhakrishnan presided over a university convocation in Assam during his visit to Guwahati. He was received upon arrival by Assam Governor Lakshman Prasad Acharya, who serves as the Governor of Assam as of September 2026. During the visit, the Vice President addressed the convocation and highlighted the importance of education, knowledge, innovation and character-building in shaping the nation's future. He encouraged students to contribute meaningfully to society and uphold democratic and constitutional values. The visit underscored the role of higher education in empowering young people and strengthening the country's development through learning, skills, research and responsible citizenship.



Key Points:

- Vice Presidential Visit Assures Focus: The Indian Vice President initiated a two-day official visit to Assam to engage in high-level public and educational programs.
- Presiding Over Academic Convocation: He attended the convocation ceremony of Srimanta Sankardeva University of Health Sciences to honor graduating medical students and researchers.

- बुनियादी ढांचे के विकास की आधारशिला: गणमान्य व्यक्तियों ने क्षेत्रीय शैक्षणिक सुविधाओं और स्थानीय बुनियादी ढांचे के विकास को बढ़ावा देने के लिए कई शैक्षणिक परियोजनाओं की आधारशिला रखी।

2. केंद्र ने पंजाब के ताप विद्युत संयंत्रों के लिए निरंतर

कोयला आवंटन सुनिश्चित किया

- ✎ देर 2026 में चरम मौसमी मांग के दौरान निर्बाध बिजली उत्पादन सुनिश्चित करने के लिए केंद्र सरकार ने पंजाब के ताप विद्युत संयंत्रों के लिए निरंतर कोयला आवंटन की गारंटी दी। इन राज्य विद्युत उत्पादन इकाइयों को मुख्य रूप से महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड से समर्पित ईंधन आवंटन प्राप्त होता था। कोल इंडिया लिमिटेड की एक प्रमुख सार्वजनिक क्षेत्र की कोयला उत्पादक सहायक कंपनी के रूप में, महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड आवश्यक ईंधन भंडार स्तर बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। रणनीतिक आपूर्ति समझौते ने बिजली अवसंरचना की स्थिरता को समर्थन दिया और उच्च खपत की अवधि के दौरान राज्य में ऊर्जा की कमी को रोका। कोयले की यह निर्बाध आपूर्ति ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करने, ईंधन रसद को अनुकूलित करने तथा निरंतर औद्योगिक और घरेलू बिजली आपूर्ति बनाए रखने के राष्ट्रीय प्रयासों को दर्शाती है।



- Laying Groundwork Infrastructure Development: The dignitaries laid foundation stones for multiple educational projects to boost regional academic facilities and local infrastructure growth.

2. Centre Guarantees Steady Coal Allocation for Punjab Thermal Units

- ✎ To ensure uninterrupted electricity generation during peak seasonal demand in late 2026, the central government guaranteed steady coal allocations for thermal power plants in Punjab. These state power generation units primarily sourced their dedicated fuel allocations from Mahanadi Coalfields Limited. As a major public sector coal-producing subsidiary of Coal India Limited, Mahanadi Coalfields Limited plays a crucial role in maintaining required fuel stock levels. The strategic supply agreement supported power infrastructure stability, preventing energy shortages across the state during high-consumption periods. This uninterrupted coal flow highlights national efforts to strengthen energy security, optimize fuel logistics, and sustain continuous industrial and domestic power supply.



Key Points:

- Strengthening Energy Supply Lines: Central authorities ensured uninterrupted coal movement to thermal stations across Punjab to sustain uninterrupted domestic power production.
- Expanding Operational Generating Capacity: Approvals were granted to establish three modern high-capacity power units, adding over two thousand megawatts of grid capacity.
- Boosting Inter-State Logistic Networks: Railway routes and supply limits were extended to smooth transportation over long distances from distant captive coal mines.

मुख्य बिंदु:

- ऊर्जा आपूर्ति श्रृंखलाओं को मजबूत करना: केंद्रीय अधिकारियों ने निर्बाध घरेलू बिजली उत्पादन बनाए रखने के लिए पंजाब के ताप विद्युत केंद्रों तक कोयले की निर्बाध आवाजाही सुनिश्चित की।
- परिचालन उत्पादन क्षमता का विस्तार: तीन आधुनिक उच्च क्षमता वाली विद्युत इकाइयों की स्थापना के लिए मंजूरी दी गई, जिससे ग्रिड क्षमता में 2000 मेगावाट से अधिक की वृद्धि हुई।
- अंतर-राज्यीय रसद नेटवर्क को बढ़ावा देना: दूर स्थित कैप्टिव कोयला खदानों से लंबी दूरी तक परिवहन को सुचारु बनाने के लिए रेलवे मार्गों और आपूर्ति सीमाओं का विस्तार किया गया।

3. वरिष्ठ भारतीय अधिकारी ने एशिया-प्रशांत डाक संघ में प्रमुख नेतृत्व भूमिका बरकरार रखी

वरिष्ठ भारतीय अधिकारी विनय प्रकाश सिंह ने सितंबर 2026 में आयोजित चौदहवीं कांग्रेस के दौरान एशिया-प्रशांत डाक संघ के महासचिव



के रूप में पुनः निर्वाचित होने के बाद अपना नेतृत्व पद बरकरार रखा। थाईलैंड के बैंकॉक में मुख्यालय वाला यह क्षेत्रीय अंतर-सरकारी निकाय एशिया-प्रशांत क्षेत्र के बत्तीस सदस्य देशों में डाक सेवाओं का समन्वय करता है और प्रशासनिक सहयोग को बढ़ावा देता है। थाई राजधानी में आयोजित अंतरराष्ट्रीय सभा ने रणनीतिक चार-वर्षीय विकास ढांचा स्थापित करने, पारंपरिक परिचालन अवसंरचनाओं का आधुनिकीकरण करने और डिजिटल डाक सेवाओं को बढ़ावा देने पर ध्यान केंद्रित किया। सिंह का सर्वसम्मत निर्वाचन भारतीय नेतृत्व में क्षेत्रीय विश्वास को दर्शाता है और विशेषीकृत डाक एजेंसी के माध्यम से क्षेत्रीय रसद, प्रशासनिक प्रशिक्षण पहलों और एकीकृत अंतरराष्ट्रीय संचार नीतियों के विस्तार में राष्ट्रीय भागीदारी को मजबूत करता है।

मुख्य बिंदु:

- प्रमुख क्षेत्रीय स्थिति सुरक्षित करना: एक भारतीय प्रतिनिधि ने एशिया-प्रशांत डाक संघ के शासी निकाय के भीतर एक प्रमुख कार्यकारी भूमिका बनाए रखी।
- डाक नेटवर्क समन्वय को बढ़ाना: गठबंधन का उद्देश्य सदस्य देशों के बीच क्षेत्रीय सीमा-पार रसद, डाक सेवाओं और अंतरराष्ट्रीय पार्सल विनिमय प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करना है।
- रणनीतिक विकास नीतियों का निर्देशन: भारत बैंकॉक से बत्तीस सदस्य देशों में क्षमता-निर्माण पहलों और डिजिटल एकीकरण नीतियों का नेतृत्व जारी रखता है।

Senior Indian Official Retains Key Leadership Role at Asian-Pacific Postal Union

Senior Indian official Vinaya Prakash Singh retained his leadership position after being re-elected as Secretary



General of the Asian-Pacific Postal Union during the Fourteenth Congress held in September 2026. Headquartered in Bangkok, Thailand, the regional intergovernmental body coordinates postal services and fosters administrative cooperation across thirty-two member nations in the Asia-Pacific region. Convening in the Thai capital, the international assembly focused on establishing a strategic four-year development framework, modernizing traditional operational infrastructures, and promoting digital postal services. Singh's unanimous election reflects regional confidence in Indian leadership and reinforces national participation in expanding regional logistics, administrative training initiatives, and unified international communications policies through the specialized postal agency.

Key Points:

- Securing Key Regional Positioning: An Indian representative maintained a primary executive role within the governing body of the Asian-Pacific Postal Union.
- Enhancing Postal Network Synergies: The alliance aims to streamline regional cross-border logistics, postal services, and international parcel exchange processes among member nations.
- Directing Strategic Development Policies: India continues to lead capacity-building initiatives and digital integration policies across thirty-two member states from Bangkok.

4. भारतीय रक्षा मंत्री ने श्रीलंका की आधिकारिक द्विपक्षीय

यात्रा शुरू की

- भारतीय रक्षा मंत्री ने पड़ोसी देशों के बीच क्षेत्रीय सुरक्षा सहयोग और रक्षा साझेदारी को मजबूत करने के लिए



श्रीलंका की आधिकारिक द्विपक्षीय यात्रा शुरू की। द्विपक्षीय वार्ता के दौरान, दोनों देशों ने अपने नियमित संयुक्त द्विपक्षीय सेना अभ्यास मित्र किरण के माध्यम से परिचालन क्षमताओं और सामरिक अंतरसंचालनीयता को बढ़ाने पर जोर दिया। चर्चाओं में हिंद महासागर क्षेत्र में प्रमुख व्यापार मार्गों को सुरक्षित करने के लिए तैयार किए गए समुद्री सुरक्षा सहयोग, आतंकवाद-रोधी रणनीतियों और संयुक्त सैन्य प्रशिक्षण कार्यक्रमों के विस्तार पर ध्यान केंद्रित किया गया। यह उच्च-स्तरीय राजनयिक यात्रा निरंतर सैन्य आदान-प्रदान और व्यापक प्रशासनिक समन्वय के माध्यम से पारस्परिक विश्वास, रणनीतिक सहयोग और क्षेत्रीय स्थिरता को बढ़ावा देते हुए भारत की पड़ोसी-प्रथम नीति के प्रति जारी प्रतिबद्धता को उजागर करती है।

मुख्य बिंदु:

- रणनीतिक उच्च-स्तरीय संवाद शुरू करना: भारतीय रक्षा मंत्री ने द्विपक्षीय सुरक्षा संबंधों को मजबूत करने के लिए कोलंबो की आधिकारिक तीन-दिवसीय राजनयिक यात्रा शुरू की।
- समुद्री रक्षा साझेदारी का विस्तार: वार्ता में क्षेत्रीय समुद्री सुरक्षा सहयोग, संयुक्त नौसैनिक प्रशिक्षण अभ्यास और रक्षा प्रौद्योगिकी आदान-प्रदान को बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित किया गया।
- क्षेत्रीय सहायता ढांचे की पुनः पुष्टि: राजनयिक संपर्क दोनों हिंद महासागर देशों के बीच पारस्परिक पड़ोसी स्थिरता और आर्थिक सुरक्षा साझेदारी को मजबूत करता है।

Indian Defence Minister Embarks on Official Bilateral Visit to Sri Lanka

- The Indian Defence Minister embarked on an official bilateral visit to Sri Lanka to strengthen regional security



cooperation and defense partnerships between the neighboring nations. During bilateral talks, both countries emphasized enhancing operational capabilities and tactical interoperability through MITRA KIRAN, their regular joint bilateral army exercise. Discussions focused on expanding maritime security cooperation, counter-terrorism strategies, and joint military training programs designed to secure key trade routes in the Indian Ocean region. This high-level diplomatic visit highlights India's ongoing commitment to its neighborhood-first policy, fostering mutual trust, strategic collaboration, and regional stability through continuous military exchange and comprehensive administrative alignment.

Key Points:

- Initiating Strategic High-Level Dialogues: The Indian Defence Minister began an official three-day diplomatic visit to Colombo to bolster bilateral security engagements.
- Expanding Maritime Defense Partnerships: Talks focused on enhancing regional maritime security cooperation, joint naval training drills, and defense technology exchanges.
- Reaffirming Regional Assistance Frameworks: The diplomatic outreach reinforces mutual neighborhood stability and economic security partnerships between the two Indian Ocean nations.

5. भारतीय वायु सेना की हेलीकॉप्टर प्रदर्शन टीम 5.

अंतरराष्ट्रीय एयर शो के लिए मिस्र पहुंची

भारतीय वायु सेना की सारंग हेलीकॉप्टर प्रदर्शन टीम सितंबर 2026 में आयोजित एल अलामीन



अंतरराष्ट्रीय एयर शो के दूसरे संस्करण में भाग लेने के लिए मिस्र पहुंची। स्वदेशी रूप से डिजाइन और निर्मित उन्नत हल्के हेलीकॉप्टर ध्रुव का संचालन करने वाली सारंग विश्व की एकमात्र पांच-हेलीकॉप्टर एरोबेटिक प्रदर्शन इकाई के रूप में विशिष्ट पहचान रखती है। एल अलामीन अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर आयोजित कार्यक्रम के दौरान टीम ने समन्वित हवाई क्रम, संरचनात्मक युद्धाभ्यास और डॉल्फिन लीप जैसी विशिष्ट प्रस्तुतियों के साथ नई प्रदर्शन तकनीकों का प्रदर्शन किया। यह भागीदारी भारत की एयरोस्पेस इंजीनियरिंग को प्रदर्शित करती है, द्विपक्षीय सैन्य सहयोग को मजबूत करती है और भारत तथा मिस्र के बीच बढ़ते रक्षा एवं राजनयिक संबंधों को सुदृढ़ करती है।

मुख्य बिंदु:

- एरोबेटिक प्रदर्शन इकाइयों की तैनाती: सारंग हेलीकॉप्टर एरोबेटिक टीम अंतरराष्ट्रीय एयरोस्पेस प्रदर्शनी में भाग लेने के लिए एल अलामीन पहुंची।
- स्वदेशी उड़ान क्षमताओं का प्रदर्शन: पायलट अंतरराष्ट्रीय दर्शकों के सामने स्वदेशी उन्नत हल्के हेलीकॉप्टर ध्रुव को उड़ाते हुए समन्वित हवाई युद्धाभ्यास करेंगे।
- द्विपक्षीय सैन्य संबंधों को मजबूत करना: यह भागीदारी भारत और मिस्र के बीच बढ़ते रक्षा कूटनीति तथा रणनीतिक एयरोस्पेस विनिर्माण साझेदारी को रेखांकित करती है।

Indian Air Force Helicopter Display Team Arrives in Egypt for International Airshow

The Sarang Helicopter Display Team of the Indian Air Force arrived in Egypt to participate in



the second edition of the El Alamein International Airshow held in September 2026. Operating the indigenously designed and manufactured Advanced Light Helicopter Dhruv, Sarang stands out as the world's only five-helicopter aerobatic display unit. During the event at El Alamein International Airport, the team performed synchronized aerial sequences, formation maneuvers, and signature routines like the Dolphin Leap alongside debuting new display techniques. This participation highlights India's aerospace engineering, strengthens bilateral military collaboration, and reinforces expanding defense and diplomatic ties between India and Egypt.

Key Points:

- Deploying Aerobatic Display Units: The Sarang helicopter aerobatic team landed at El Alamein to participate in an international aerospace exhibition.
- Showcasing Indigenous Flying Capabilities: Pilots will execute synchronized aerial maneuvers flying the indigenous Advanced Light Helicopter Dhruv before international audiences.
- Strengthening Bilateral Military Ties: The participation underscores growing defense diplomacy and strategic aerospace manufacturing partnerships between India and Egypt.

6. केंद्रीय खेल मंत्री ने गुजरात में नशीली पदार्थों के दुरुपयोग से निपटने के लिए फिटनेस अभियान का नेतृत्व किया

युवा लोगों के बीच स्वस्थ और नशामुक्त जीवनशैली को बढ़ावा देने के उद्देश्य से केंद्रीय युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने गुजरात में राष्ट्रीय फिटनेस और नशा-विरोधी अभियान का नेतृत्व किया। अभियान में नशीली पदार्थों के दुरुपयोग को हतोत्साहित करने और स्वस्थ विकल्पों को प्रोत्साहित करने के प्रभावी साधनों के रूप में फिटनेस, खेल और शारीरिक गतिविधियों के उपयोग पर ध्यान केंद्रित किया गया। कार्यक्रम के दौरान एक मजबूत और स्वस्थ राष्ट्र के निर्माण में युवाओं की महत्वपूर्ण भूमिका पर जोर दिया गया। इस पहल ने नशीली पदार्थों के दुरुपयोग के खिलाफ जागरूकता के साथ खेल और फिटनेस को जोड़ने के सरकार के प्रयासों को उजागर किया। इसने शारीरिक गतिविधियों में अधिक भागीदारी को भी प्रोत्साहित किया और यह संदेश दिया कि सक्रिय जीवनशैली बेहतर शारीरिक स्वास्थ्य, मानसिक कल्याण और जिम्मेदार नागरिकता में योगदान दे सकती है।



मुख्य बिंदु:

- साइकिलिंग कार्यक्रम को रवाना करना: केंद्रीय खेल मंत्री ने युवाओं के बीच स्वस्थ जीवन को बढ़ावा देने के लिए सूरत में एक विशाल साइकिलिंग अभियान का नेतृत्व किया।
- नशीली पदार्थों की लत के खिलाफ अभियान: यह पहल नशीली पदार्थों के दुरुपयोग को हतोत्साहित करने और युवाओं की ऊर्जा को रचनात्मक खेल गतिविधियों की ओर निर्देशित करने के राष्ट्रीय प्रयासों के अनुरूप थी।
- खेलों के माध्यम से युवाओं को संगठित करना: हजारों स्थानीय विद्यार्थियों, नागरिकों और प्रमुख खिलाड़ियों ने रैली में भाग लिया तथा नशा-विरोधी सामुदायिक संकल्प लिया।

Union Sports Minister Leads Fitness Campaign in Gujarat to Counter Substance Abuse

Union Minister for Youth Affairs and Sports Mansukh Mandaviya led a national fitness and anti-drug campaign in Gujarat aimed at promoting a healthy and drug-free lifestyle among young people. The campaign focused on using fitness, sports and physical activity as effective tools to discourage substance abuse and encourage healthier choices. During the programme, emphasis was placed on the important role of youth in building a stronger and healthier nation. The initiative highlighted the Government's efforts to combine sports and fitness with awareness against substance abuse. It also encouraged greater participation in physical activities and promoted the message that an active lifestyle can contribute to better physical health, mental well-being and responsible citizenship.



Key Points:

- Flagging Off Cycling Event: The Union Sports Minister spearheaded a massive cycling drive in Surat to promote healthy living among youth.
- Campaigning Against Substance Addiction: The initiative aligned with national efforts to discourage drug abuse and channel youth energy toward constructive athletic pursuits.
- Mobilizing Youth Through Sports: Thousands of local students, citizens, and prominent athletes joined the rally to take anti-addiction community pledges.

7. पर्यावरण मंत्रालय ने ग्रामीण सीमा बस्तियों के विकास ढांचे की समीक्षा की

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने भारत की अंतरराष्ट्रीय सीमाओं के साथ स्थित ग्रामीण बस्तियों के विकास ढांचे की समीक्षा की, जिसमें पारिस्थितिक पुनर्स्थापन, सतत विकास और बेहतर ग्रामीण बुनियादी ढांचे पर ध्यान केंद्रित किया गया। इस पहल का उद्देश्य नाजुक पारिस्थितिक तंत्रों की रक्षा करते हुए और आजीविका के अवसरों को बढ़ावा देते हुए सीमा समुदायों को मजबूत करना है। ढांचे के अंतर्गत शामिल क्षेत्रों में, दिए गए विकल्पों में अरुणाचल प्रदेश भारत की स्थलीय सीमा की अधिकतम लंबाई साझा करता है और इसलिए विकासात्मक सहायता का एक प्रमुख केंद्र है। समीक्षा में संवेदनशील सीमा क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे के विकास और पर्यावरण संरक्षण के बीच संतुलन बनाए रखने की आवश्यकता पर प्रकाश डाला गया। इसमें समुदाय की भागीदारी, सतत संसाधन प्रबंधन और दूरस्थ सीमा बस्तियों में रहने वाले लोगों के जीवन स्तर में सुधार पर भी जोर दिया गया।

मुख्य बिंदु:

- सीमा क्षेत्र के विकास का मूल्यांकन: पर्यावरण मंत्रालय ने दूरस्थ उत्तरी सीमा बस्तियों में जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाने के उद्देश्य से सतत विकास रणनीतियों की समीक्षा की।
- पर्यावरण-अनुकूल बुनियादी ढांचा योजनाओं को मजबूत करना: व्यापक ढांचे सीमा क्षेत्रों में आवश्यक बुनियादी ढांचे और सार्वजनिक उपयोगिता विकास के साथ पारिस्थितिक संरक्षण के संतुलन पर ध्यान केंद्रित करते हैं।
- स्थानीय समुदाय की भागीदारी को एकीकृत करना: कार्यक्रम मॉडल अंतरराष्ट्रीय स्थलीय सीमाओं के साथ दीर्घकालिक आर्थिक मजबूती को बढ़ावा देने के लिए युवाओं की भागीदारी और स्थानीय शासन को प्राथमिकता देते हैं।

Environment Ministry Reviews Development Framework for Rural Border Settlements

The Ministry of Environment, Forest and Climate Change reviewed the development framework for rural settlements located along India's international borders, focusing on ecological restoration, sustainable development and improved rural infrastructure. The initiative aims to strengthen border communities while protecting fragile ecosystems and promoting livelihood opportunities. Among the regions covered under the framework, Arunachal Pradesh shares the maximum length of India's land border among the listed options and is therefore a major focus of the developmental support. The review highlighted the need to balance infrastructure development with environmental conservation in sensitive border areas. It also emphasized community participation, sustainable resource management and improved living conditions for people residing in remote border settlements.

Key Points:

- Evaluating Border Area Growth: The Environment Ministry reviewed sustainable development strategies aimed at improving quality of life in remote northern border settlements.
- Strengthening Eco-Friendly Infrastructure Plans: Comprehensive frameworks focus on balancing ecological preservation with vital infrastructure and public utility development in border zones.
- Integrating Local Community Participation: Program models prioritize youth engagement and local governance to foster long-term economic resilience along international land boundaries.

8. केंद्रीय मंत्री ने गैर-महानगरीय शहरों में उभरती प्रौद्योगिकी उद्यमिता पर प्रकाश डाला

केंद्रीय मंत्री ने भारत भर के श्रेणी-2 और श्रेणी-3 शहरों में प्रौद्योगिकी उद्यमिता और नवाचार को बढ़ावा देने वाली एक पहल के रूप में नेक्स्टजेन



स्टार्टअप चुनौती पर प्रकाश डाला। कार्यक्रम का उद्देश्य युवा नवप्रवर्तकों, उद्यमियों और प्रौद्योगिकी-संचालित उद्यमों को उभरते शहरों में प्रोत्साहित करके प्रमुख महानगरीय केंद्रों से परे मजबूत स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र तैयार करना है। यह होनहार स्टार्टअप को नवीन समाधान विकसित करने, सहायता नेटवर्क तक पहुंच प्राप्त करने और स्थानीय आर्थिक विकास में योगदान करने के अवसर प्रदान करने पर केंद्रित है। यह पहल देश के बढ़ते स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र के लाभों का विस्तार करने और नवाचार के विकेंद्रीकरण के लिए सरकार के व्यापक प्रयासों को दर्शाती है। गैर-महानगरीय क्षेत्रों में उद्यमशील प्रतिभा को बढ़ावा देकर, इसका उद्देश्य नए अवसर पैदा करना, नवाचार केंद्रों को मजबूत करना और पूरे भारत में समावेशी प्रौद्योगिकी-आधारित विकास का समर्थन करना है।

मुख्य बिंदु:

- स्टार्टअप विकास की प्रवृत्तियों पर प्रकाश डालना: केंद्रीय मंत्री ने कहा कि आधे से अधिक नए नवोन्मेषी उद्यम अब श्रेणी-दो और श्रेणी-तीन शहरों से उत्पन्न होते हैं।
- राष्ट्रीय नवाचार पारिस्थितिकी तंत्र का विकेंद्रीकरण: सरकारी कार्यक्रम स्थापित महानगरीय वाणिज्यिक केंद्रों से आगे छोटे शहरों तक अनुसंधान नेटवर्क और स्टार्टअप वित्तपोषण का विस्तार कर रहे हैं।
- अनुसंधान और उद्योग के बीच सेतु बनाना: पहलों का उद्देश्य स्थानीय शैक्षणिक प्रयोगशालाओं को वाणिज्यिक उद्योगों से जोड़ना है ताकि क्षेत्रीय अनुसंधान को व्यवहार्य उत्पादों में परिवर्तित किया जा सके।

Union Minister Highlights Emerging Tech Entrepreneurship in Non-Metropolitan Cities

The Union Minister highlighted the NEXTGEN Startup Challenge as an initiative aimed at promoting technology



entrepreneurship and innovation in Tier-2 and Tier-3 cities across India. The programme seeks to create stronger startup ecosystems beyond major metropolitan centres by encouraging young innovators, entrepreneurs and technology-driven enterprises in emerging cities. It focuses on providing opportunities for promising startups to develop innovative solutions, access support networks and contribute to local economic growth. The initiative reflects the Government's broader efforts to decentralise innovation and expand the benefits of the country's growing startup ecosystem. By nurturing entrepreneurial talent in non-metropolitan areas, it aims to create new opportunities, strengthen innovation hubs and support inclusive technology-led development across India.

Key Points:

- Highlighting Startup Growth Trends: The Union Minister stated that over half of new innovative enterprises now originate from Tier-two and Tier-three cities.
- Decentralizing National Innovation Ecosystems: Government programs are expanding research networks and startup funding beyond established metropolitan commercial hubs into smaller towns.
- Bridging Research And Industry: Initiatives aim to connect local academic laboratories with commercial industries to translate regional research into viable products.

9. चंडीगढ़ ने जैव विविधता शासन ढांचे पर राष्ट्रीय सभा की मेजबानी की

चंडीगढ़ ने जैव विविधता अधिनियम, 2002 के प्रावधानों के तहत जैव विविधता शासन पर केंद्रित एक राष्ट्रीय सभा की मेजबानी की। सभा में हितधारकों ने जैव विविधता संरक्षण को मजबूत करने, जैविक संसाधनों के सतत उपयोग और उनके उपयोग से होने वाले लाभों के उचित एवं समान वितरण पर चर्चा की। यह ढांचा राष्ट्रीय, राज्य और स्थानीय स्तर के संस्थानों से जुड़े समन्वित प्रयासों के माध्यम से प्रभावी जैव विविधता शासन को समर्थन देने का प्रयास करता है। चर्चाओं में सामुदायिक भागीदारी के महत्व और जैविक संसाधनों तथा उनसे जुड़े पारंपरिक ज्ञान की रक्षा में स्थानीय निकायों की भूमिका पर भी प्रकाश डाला गया। यह पहल वर्तमान और भावी पीढ़ियों के लिए देश की समृद्ध जैव विविधता के सतत संसाधन प्रबंधन और जिम्मेदार उपयोग को बढ़ावा देते हुए जैव विविधता संरक्षण को मजबूत करने के भारत के निरंतर प्रयासों को दर्शाती है।



Chandigarh Hosts National Assembly on Biodiversity Governance Frameworks

Chandigarh hosted a National Assembly focused on biodiversity governance under the provisions of the Biological Diversity Act, 2002. The assembly brought together stakeholders to discuss strengthening biodiversity conservation, sustainable use of biological resources and fair and equitable sharing of benefits arising from their use. The framework seeks to support effective biodiversity governance through coordinated efforts involving national, state and local-level institutions. Discussions also highlighted the importance of community participation and the role of local bodies in protecting biological resources and associated traditional knowledge. The initiative reflects India's continued efforts to strengthen biodiversity conservation while ensuring sustainable resource management and promoting responsible utilisation of the country's rich biological diversity for present and future generations.



मुख्य बिंदु:

- राष्ट्रीय जैव विविधता सम्मेलन का उद्घाटन: चंडीगढ़ ने स्थानीय शासन को मजबूत करने के लिए राज्य और केंद्रशासित प्रदेश जैव विविधता बोर्डों की सोलहवीं राष्ट्रीय बैठक की मेजबानी की।
- जमीनी स्तर की पारिस्थितिक समितियों को मजबूत करना: अधिकारियों ने पारंपरिक पर्यावरणीय ज्ञान और संरक्षण का दस्तावेजीकरण करने के लिए 2 लाख से अधिक स्थानीय समितियों को कार्यात्मक बनाने पर जोर दिया।
- निष्पक्ष सामुदायिक लाभों का वितरण: राष्ट्रीय प्राधिकरण ने लाभ-साझाकरण तंत्र के तहत स्थानीय समुदायों और किसानों को 200 करोड़ रुपये से अधिक वितरित किए।

Key Points:

- Inaugurating National Biodiversity Conference: Chandigarh hosted the sixteenth national meeting of state and union territory biodiversity boards to strengthen local governance.
- Strengthening Grassroots Ecological Committees: Officials emphasized making over two lakh local committees functional to document traditional environmental knowledge and conservation.
- Distributing Fair Community Benefits: The national authority disbursed over two hundred crore rupees to local communities and farmers under benefit-sharing mechanisms.

10. राष्ट्रीय कार्यशाला ने हरियाणा में पक्षी संरक्षण रणनीतियों पर ध्यान केंद्रित किया

हरियाणा में आयोजित राष्ट्रीय पक्षी संरक्षण कार्यशाला के दौरान यह रेखांकित किया गया कि भारत मध्य एशियाई फ्लाईवे के साथ प्रवासी पक्षियों के लिए एक महत्वपूर्ण शीतकालीन निवास स्थल है। कार्यशाला में महत्वपूर्ण आवासों और आर्द्रभूमियों में विशेष रूप से प्रवासी और स्थानीय पक्षी प्रजातियों के संरक्षण एवं सुरक्षा के लिए रणनीतियों को मजबूत करने पर ध्यान केंद्रित किया गया। चर्चाओं में समन्वित संरक्षण प्रयासों, आवास प्रबंधन, पक्षी आबादी की निगरानी और हितधारकों के बीच अधिक जागरूकता पर जोर दिया गया। मध्य एशियाई फ्लाईवे एक विशाल भौगोलिक क्षेत्र को कवर करता है और अनेक प्रवासी पक्षी प्रजातियों द्वारा उपयोग किए जाने वाले प्रजनन तथा शीतकालीन क्षेत्रों को जोड़ता है। इस फ्लाईवे के अंतर्गत भारत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है क्योंकि यह महत्वपूर्ण शीतकालीन और पड़ाव वाले आवास उपलब्ध कराता है, जिससे प्रवासी पक्षी आबादी और उनके पारिस्थितिक तंत्रों की सुरक्षा के लिए प्रभावी संरक्षण उपाय आवश्यक हो जाते हैं।



मुख्य बिंदु:

- गिद्ध संरक्षण शिखर सम्मेलन की मेजबानी: अंतरराष्ट्रीय गिद्ध जागरूकता दिवस पर पंचकूला में संकट से पुनर्प्राप्ति विषयक एक राष्ट्रीय कार्यशाला आयोजित की गई।
- संरक्षित पक्षी क्षेत्रों का विस्तार: पर्यावरण नेताओं ने घटती जंगली गिद्ध आबादी को पुनर्स्थापित करने के लिए सुरक्षित क्षेत्र और अधिक सुरक्षित पशु चिकित्सा पद्धतियां बनाने का आह्वान किया।
- सफल प्रजनन पहलों पर प्रकाश डालना: पिंजौर संरक्षण केंद्र ने सफलतापूर्वक सैकड़ों पक्षियों को आश्रय दिया और जंगली पुनर्प्रवेश प्रयासों के लिए दर्जनों चूजों का प्रजनन किया।

10. National Workshop Focuses on Avian Conservation Strategies in Haryana

India serves as an important wintering ground for migratory birds along the Central Asian Flyway, which was highlighted during the National Workshop on Avian Conservation held in Haryana. The workshop focused on strengthening strategies for the conservation and protection of migratory and resident bird species, particularly across important habitats and wetlands. Discussions emphasised coordinated conservation efforts, habitat management, monitoring of bird populations and greater awareness among stakeholders. The Central Asian Flyway covers a vast geographical region and connects breeding and wintering areas used by numerous migratory bird species. India plays a crucial role within this flyway by providing important wintering and stopover habitats, making effective conservation measures essential for protecting migratory bird populations and their ecosystems.



Key Points:

- Hosting Vulture Conservation Summit: A national workshop titled From Crisis to Recovery was held in Panchkula on International Vulture Awareness Day.
- Expanding Protected Avian Zones: Environment leaders called for creating safe zones and safer veterinary practices to restore declining wild vulture populations.
- Highlighting Successful Breeding Initiatives: The Pinjore conservation center successfully housed hundreds of birds and bred dozens of chicks for wild reintroduction efforts.

दैनिक समसामयिक

DAILY

CURRENT AFFAIRS

MCQs

प्रश्नोत्तरी

Q1. मध्य एशियाई फ्लाईवे के संदर्भ में भारत की प्रमुख भूमिका क्या है?

- (a) केवल प्रजनन स्थल के रूप में कार्य करना
- (b) प्रवासी पक्षियों के लिए महत्वपूर्ण शीतकालीन निवास स्थल के रूप में कार्य करना
- (c) केवल पक्षियों के लिए कृत्रिम आवास बनाना
- (d) केवल समुद्री पक्षियों के लिए आवास उपलब्ध कराना

Q2. सितंबर 2026 में चंडीगढ़ में आयोजित जैव विविधता शासन से संबंधित राष्ट्रीय सभा किस अधिनियम के प्रावधानों के तहत आयोजित की गई?

- (a) पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986
- (b) वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 1972
- (c) जैव विविधता अधिनियम, 2002
- (d) वन संरक्षण अधिनियम, 1980

Q3. नेक्स्टजेन स्टार्टअप चुनौती का प्रमुख उद्देश्य क्या है?

- (a) केवल कृषि उत्पादन बढ़ाना
- (b) केवल महानगरों में स्टार्टअप स्थापित करना
- (c) श्रेणी-2 और श्रेणी-3 शहरों में प्रौद्योगिकी उद्यमिता और नवाचार को बढ़ावा देना
- (d) केवल सरकारी कर्मचारियों को तकनीकी प्रशिक्षण देना

Q4. दिए गए विकल्पों में से किस राज्य की भारत के साथ सबसे लंबी स्थलीय अंतरराष्ट्रीय सीमा है?

- (a) लद्दाख
- (b) हिमाचल प्रदेश
- (c) उत्तराखंड
- (d) अरुणाचल प्रदेश

Q1. What is India's major role in the context of the Central Asian Flyway?

- (a) It serves only as a breeding ground
- (b) It serves as an important wintering habitat for migratory birds
- (c) It only creates artificial habitats for birds
- (d) It provides habitats only for marine birds

Q2. Under the provisions of which Act was the national assembly on biodiversity governance held in Chandigarh in September 2026?

- (a) Environment Protection Act, 1986
- (b) Wildlife Protection Act, 1972
- (c) Biological Diversity Act, 2002
- (d) Forest Conservation Act, 1980

Q3. What is the primary objective of the NextGen Startup Challenge?

- (a) To increase only agricultural production
- (b) To establish startups only in metropolitan cities
- (c) To promote technology entrepreneurship and innovation in Tier-2 and Tier-3 cities
- (d) To provide technical training only to government employees

Q4. Among the following, which state shares the longest land-based international border with India?

- (a) Ladakh
- (b) Himachal Pradesh
- (c) Uttarakhand
- (d) Arunachal Pradesh

- Q5. 2026 के अंत में गुजरात में नशीली पदार्थों के दुरुपयोग के विरुद्ध फिटनेस अभियान का नेतृत्व किस केंद्रीय मंत्री ने किया ?
 (a) मनसुख मांडविया (b) किरन रिजिजू
 (c) हर्ष सांघवी (d) अनुराग ठाकुर
- Q6. सितंबर 2026 में मिस्त्र के एल अलामीन अंतरराष्ट्रीय एयर शो में भारतीय वायु सेना की किस हेलीकॉप्टर एरोबेटिक टीम ने भाग लिया ?
 (a) सूर्यकिरण (b) सारंग
 (c) रुद्र (d) त्रिशूल
- Q7. भारत और श्रीलंका के बीच नियमित संयुक्त द्विपक्षीय सेना अभ्यास का नाम क्या है ?
 (a) संप्रति (b) सूर्यशक्ति
 (c) मित्रकिरण (d) गरुड़शक्ति
- Q8. एशिया-प्रशांत डाक संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है ?
 (a) नई दिल्ली, भारत (b) कुआलालंपुर, मलेशिया
 (c) मनीला, फिलीपींस (d) बैंकॉक, थाईलैंड
- Q9. पंजाब के ताप विद्युत संयंत्रों को मुख्य रूप से किस कोयला उत्पादक सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम से कोयला आवंटन प्राप्त होता है ?
 (a) महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड
 (b) वेस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड
 (c) नेवेली लिग्नाइट कॉर्पोरेशन
 (d) सिंगरेनी कोलियरीज कंपनी लिमिटेड
- Q10. सितंबर 2026 तक असम के राज्यपाल के रूप में कौन कार्यरत थे ?
 (a) गुलाब चंद कटारिया
 (b) लक्ष्मण प्रसाद आचार्य
 (c) बनवारीलाल पुरोहित
 (d) रमेश बैस

- Q5. Which Union Minister led the fitness campaign against drug abuse in Gujarat in late 2026?
 (a) Mansukh Mandaviya
 (b) Kiren Rijiju
 (c) Harsh Sanghavi
 (d) Anurag Thakur
- Q6. Which helicopter aerobatic team of the Indian Air Force participated in the El Alamein International Air Show in Egypt in September 2026?
 (a) Surya Kiran
 (b) Sarang
 (c) Rudra
 (d) Trishul
- Q7. What is the name of the regular joint bilateral army exercise between India and Sri Lanka?
 (a) Sampriti
 (b) Surya Shakti
 (c) Mitra Shakti
 (d) Garuda Shakti
- Q8. Where is the headquarters of the Asian-Pacific Postal Union located?
 (a) New Delhi, India
 (b) Kuala Lumpur, Malaysia
 (c) Manila, Philippines
 (d) Bangkok, Thailand
- Q9. Punjab's thermal power plants primarily receive coal allocation from which coal-producing public sector undertaking?
 (a) Mahanadi Coalfields Limited
 (b) Western Coalfields Limited
 (c) Neyveli Lignite Corporation
 (d) Singareni Collieries Company Limited
- Q10. Who was serving as the Governor of Assam as of September 2026?
 (a) Gulab Chand Kataria
 (b) Lakshman Prasad Acharya
 (c) Banwarilal Purohit
 (d) Ramesh Bais

उत्तरमाला (Answer Key)

- 1 (B) 2 (C) 3 (C) 4 (D) 5 (A) 6 (B) 7 (C) 8 (D) 9 (A) 10 (B)

